ओपट कास्ट माइनिंग के साथ साथ अव्यवस्थित खनन भी किया जा रहा है। व्यर्थ अवशेष व मिट्टी के लुढकाने से नीचे की सुन्दर घाटी भू-क्षरण से प्रभावित हो रही है। लैंड रीक्लेमेशन के कार्य को भी नहीं किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के प्रदूषण से निकटवर्ती क्षेत्रों की वन संपत्ति नष्ट हो रही है।

मैं इस अव्यवस्थित खनन व प्रदूषण को रोकने हेतु राज्य सरकार के ध्यान में ला चुका हूं। मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान भी लोकसभा में दो बार प्रश्न पूछ कर इस ओर दिला चुका हूं। परंतु अभीष्ट अभी भी अपेक्षित है। मैं पुन: केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

1208 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

(vii) Need to Apply Laws Relating to Minimum Wages and Working Conditions to Bidi Workers

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (Guna): Chanderi, Guna, Sagar, Damoh, Jabalpur and Raipur etc. are big centres of bidi industry in M.P. Lakhs of workers, including a large number of women and children are employed in it. These workers are, however, an exploited lot. Though they are busy from dawn to dusk in rolling bidis, the wages they receive are quite low. A fairly large number of bidi workers become victims of tuberculosis and tend to develop hunch-back tendencies. The condition of bidi workers scattered in rural areas is still worse. They are at the mercy of 'sattedars' who act as agents of bidi units. They supply tobacco and tendu leaves to rural bidi workers and assess the quality of the bidis produced. They invariably reject at least ten per cent of a worker's output as 'sub-standard'' and thus deprive him or her of full payment for the output. Not much effort has been made so far to free the workers from the stranglehold of satterdars, as the Bidi Kings do not want to discontinue the Sattedari system. It enables them to escape responsibility for paying fair wages and providing various facilities to workers.

I, therefore, urge upon the Government to take steps to ensure that :—

(i) the laws regarding minimum wages and working conditions are enforced in bidi-making establishments ; and

(ii) the cooperatives of bidi-workers are set up to enable them to get adequate return for their labour.

(vii) Non-availability of Drinking Water and Electricity in Bihar

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : बिहार में विद्युत संकट स्थायी सा हो गया है। इधर एक सप्ताह के अन्दर इस संकट के कारण लगभग सभी जिलों के मुख्यालयों में पेयजल एवं रोशनी नहीं मिल रही है। रांची की हालत विगत 24 घन्टों से अति दयनीय हो गयी है। पेयजल एकदम बंद है। हैवी इंजीनियरी काम्पलेक्स को 40 मैगावाट के स्थान पर सिर्फ 10 मैगावाट बिजली मिल रही है। इसका उत्पादन भी संकट में पड़ गया है। इसके अतिरिक्त लगभग राज्य का सारा उद्योग बंद सा हो गया है।

बिजली के अभाव में विगत वर्ष खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है। अभी रबी लगाने का समय है तो बिजली नहीं है। यह फसल भी नष्ट होने वाली हैं।

जब बिहार में विद्युत की क्षमता 945 मैगावाट है तो सप्लाई सिर्फ 150 मेगावाट की ही क्यों है ? की उच्चस्तरीय जांच करायी जाय और तुरंत उचित मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की जाय।